संख्या-13/2024/521/22-4-2023-133-बी-98-284961

प्रेषक,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ : दिनांक 15 फरवरी, 2024**

विषयः- जनपद हाथरस में जिला कारागार के निर्माण हेतु सम्पूर्ण परियोजना एवं रू0 18494.29 लाख की लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-24382/नम-1/41/हाथरस/2023, दिनांक 28.07.2023 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हाथरस में जिला कारागार के निर्माण हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 18494.29 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू0 4620.00 लाख (रूपया छियालीस करोड़ बीस लाख मात्र) निम्न सारणी के स्तम्भ-5 में अंकित लागत की धनराशि रुपये 18494.29 लाख के सापेक्ष स्तम्भ-6 में अंकित प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रूपये 4620.00 लाख (रूपया छियालीस करोड़ बीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कारागार का नाम	कार्य का नाम	कार्यदायी संस्था	कार्य की लागत	वित्तीय वर्ष 2023-24 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जिला कारागार हाथरस	कारागार का निर्माण	लोक निर्माण विभाग	18494.29	4620.00
			योगः-	**18494.29**	**4620.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरण क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप महानिरीक्षक, कारागार द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाना होगा।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(5) कार्ययोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि बिना पी0एफ0ए0डी0 के पूर्व अनुमोदन के प्राप्त किये बिना नही किया जायेगा।

(6) निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण कर उसका कब्जा विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा। महानिरीक्षक, कारागार परियोजना के क्रियान्वयन में टाइम ओवर रन कास्ट ओवर रन को नियंत्रित करने हेतु वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 21.06.2017 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(9) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 में निहित प्राविधानित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अवशेष धनराशि स्वीकृत की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 26.08.2014 एवं दिनांक 15.06.2018 के अनुसार परीक्षणोपरान्त सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

(10) लेबर सेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(11) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा उपकरणों/सामग्री का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से किया जायेगा।

(12) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा कार्यदायी संस्था को जो धनराशि अवमुक्त की जायेगी, वह कार्य की आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। कार्यदायी संस्था को पूर्व में दी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत का उपभोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाय।

(13) प्रायोजना हेतु जी0एस0टी0 की वास्तविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(14) क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें। चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं उनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक ए माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अन्तर आना स्वाभावित है।

(15) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के प्श्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाए।

(16) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृतियों से संबंधित वित्तीय प्रबन्धन के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के नवीनतम शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17.05.2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19.05.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2024 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

(18) ई0पी0सी0 मोड की प्रायोजनाओं का फण्ड फ्लो तैयार कर उसके अनुसार धनराशि की व्यवस्था करते हुए निर्माण कार्य कराया जाय, जिससे ई0पी0सी0 मोड की प्रायोजनाओं में पुनरीक्षण की स्थिति उत्पन्न न हो सके।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) प्रायोजना की लागत रू0 50.00 करोड़ से अधिक है। वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-19/2019/बी-2-615/दस-219, दिनांक-13.12.2019 के अनुसार ई0पी0सी0 मोड द्वारा कराया जाना होगा। अत: लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में ई0पी0सी0 मोड की समस्त प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(20) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनुमन्य कर दी गयी है। प्रशासकीय विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(21) प्रायोजना प्रस्ताव का परीक्षण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/ बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है।

(22) लागत का आंकलन प्रस्तावित मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(23) गैर मानकीकृत प्रस्तावित क्षेत्रफल के आधार पर किये जा रहे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग स्वयं निर्णय लेते हुए अपने उत्तरदायित्व पर कार्य करेंगे।

(24) प्रायोजनान्तर्गत कतिपय कार्यमद यथा किचेन, हास्पिटल सेफ्टी,फर्नीचर, सी0सी0टी0वी0 सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम, यू0पी0एस0, बूम बैरियर, फेन्सिंग एण्ड सेफ्टी कवर, पी0ए0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स सिस्टम,वीडियो कार्यफ्रेंस सिस्टम, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, एक्स-रे बैगेज स्कैनर, हेण्ड हेल्ड मेटल डिटेक्टर, वाकी-टॉकी की लागत अनुमन्य नहीं की गयी है। प्रशासकीय विभाग इन कार्यमदों पर पृथक पत्रावली के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेंगे।

(25) प्रश्नगत निर्माण कार्य की विशालता को देखते हुए प्रभाग का यह भी सुझाव है कि प्रयोजनान्तर्गत निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यों की प्रगति के सतत् अनुश्रवण हेतु शासन स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 46,20,00,000 (रुपये छियालीस करोड़ बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008000800 कारागारों का निर्माण **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-12-222-X-2023-24-दिनांक: 13-02-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

संख्या-13/2024/521(1)/22-4-2023-133-बी-98-284961, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज |

(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(4) जिलाधिकारी, हाथरस।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) निदेशक, वित्तीय सांख्कीयि निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(8) वित्त नियंत्रक, कारागार, मुख्यालय, लखनऊ।
(9) वित्त (व्यंय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय व्यायक) अनुभाग-1/2
(10) गाई फाईल।

आज्ञा से,

अभय कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.g

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।